www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 05 | अंक – 08 | जौनपुर, शुक्रवार, 21 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

बिहार की राजकोषीय हालत खराब, भारी कर्ज में डूबा राज्य – तेजस्वी यादव

पटना, (एजेंसी)। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दावा किया कि बिहार की राजकोषीय स्थिति बेहद दयनीय और चिंताजनक हो गई है। राज्य भारी कर्ज के बोझ तले दब चुका है और कुल सार्वजनिक ऋण में चार गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार को गंभीर आर्थिक संकट की ओर धकेला जा रहा है। उनके मुताबिक, राज्य की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ठेकेदारों के बकाये और विकास कार्यों के लिए समय पर पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि छात्रों को मिलने वाले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की राशि घटाई गई है और छात्रवृत्ति को समाप्त किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास व्यय प्रबंधन, ऋण प्रबंधन और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की कोई स्पष्ट समझ और दीर्घकालिक योजना नहीं है। तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा राज्य का राजस्व घाटा बढ़ रहा है और कर्ज उससे भी तेज गति से बढ़ रहा है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार का राजकोषीय घाटा सबसे अधिक रहा और यह जीएसडीपी का 5.8 प्रतिशत था। उन्होंने कहा कि ऊंचे राजकोषीय घाटे के साथ भारी कर्ज का बोझ राज्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों और खर्च के बीच संतुलन नहीं होने का भी उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्व सृजन और संग्रह बढ़ाने, बजटीय प्रबंधन सुधारने तथा राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस दीर्घकालिक योजना नहीं है।

युवाओं की क्षमता को दिशा देने के लिए सरकार और विश्वविद्यालयों में बेहतर तालमेल जरूरी - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीतियां बनाने में नये दृष्टिकोण लाने के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक सहयोग का बृहस्पतिवार को आह्वान किया। मोदी ने युवा पीढ़ी तक पहुंचने की अपनी कोशिशों के तहत कहा कि इस तरह के व्यापक जुड़ाव से नए और अनोखे विचार सामने आ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ तीसरी उच्च–स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया और कोविड–19 महामारी तथा पश्चिम एशिया संकट के अनुभव का उल्लेख किया, जब अलग–अलग विभागों के अधिकारियों ने मिलकर काम किया था। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नीति–निर्माण में नए नजरिए के लिए सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच अधिक संवाद का आह्वान किया। प्रधानमंत्री की ये टिप्पणियां पिछले महीने दिल्ली के जंतर–मंतर और देश के अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के प्रश्नपत्र लीक को लेकर हुए छात्रों के विरोध–प्रदर्शनों के बीच आई। छात्रों के विरोध–प्रदर्शनों के कारण धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार सोशल मीडिया के जरिए छात्रों को संदेश दिया। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी एक पोस्ट में कहा कि सचिवों के साथ हुई बैठक में उन्होंने आधारभूत अवसंरचना और संपर्क, सुरक्षा और विदेश मामलों से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा, ''डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के प्रभावी इस्तेमाल, विश्वविद्यालयों के साथ अधिक जुड़ाव और अलग–अलग क्षेत्रों में अनुसंधान और नवोन्मेष पर अधिक ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि सचिवों को तात्कालिक मुद्दों और सांख्यिकी के बारे में सोचने के साथ–साथ देश के भविष्य को आकार देने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। उन्होंने रेखांकित किया।

सीमाएं सुरक्षित हुए बिना भारत सुरक्षित नहीं रह सकता – गृह मंत्री अमित शाह

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जब तक सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही भारत सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने कहा कि उनके कई बार अनुरोध करने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भारत–बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। अमित शाह ने कहा कि राज्य के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) या सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सिलीगुड़ी स्थित एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में कहा, ''मैंने बीएसएफ द्वारा सीमा पर बाड़ लगाए जाने के लिए जमीन देने की कई बार गुहार लगाई लेकिन (पूर्व मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी ने इसे अनसुना कर दिया। मैं सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए 1,129 एकड़ जमीन की मांग 2014 से कर रहा था। राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद ही हमें यह जमीन मिली।'' उन्होंने कहा कि एसएसबी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और सीमावर्ती बलों के समारोहों से पूर्व मुख्यमंत्रियों की दूरी ने गलत संदेश दिया। गृह मंत्री ने कहा कि वह आजादी के बाद देश में बनीं पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं दिए जाने से दुखी थे।

सिंधिया ने किया ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत, डिजिटल सहयोग बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पुणे में गुरुवार को 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से पहले डिजिटल ब्रिक्स फोरम और एक्स्पो का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देशों की सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविद, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदस्य देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया। इस दौरान 'सुदृढ़ भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव (आईसीटी)' विषय पर ब्रिक्स संचार मंत्रियों की मंत्री–स्तरीय अनौपचारिक चर्चा भी हुई। डिजिटल ब्रिक्स फोरम ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक का बहु–हितधारक मंच है, जिसे 2021 में भारत की मेजबानी में आयोजित 7वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक के दौरान स्थापित किया गया था। फोरम में सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों ने डिजिटल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडलों के स्वागत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पुणे पिछले कुछ दिनों में केवल सरकारों के ही नहीं, बल्कि विचारों, नवाचार और साझा आकांक्षाओं के मिलन का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ग्रुप, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर नेटवर्क्स, डिजिटल ब्रिक्स टास्क फोर्स और डिजिटल ब्रिक्स फोरम के माध्यम से विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं ने समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के तरीकों पर काम किया है।

सर्वोदय विद्यालयों के बेहतर संचालन के लिए बड़े बदलाव बेहद जरूरी – सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में व्यवस्थित संचालन में बड़े बदलाव की जरूरत बताई है। बृहस्पतिवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में सीएम ने विद्यालयों से जुड़ी स्पष्ट नियमावली तैयार करने, शिक्षकों के खाली पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने और आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन और संचालन ज्यादा व्यवस्थित ढंग से करने के लिए सोसाइटी के गठन के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित थे, जबकि वर्ष 2025–26 तक इनकी संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इनमें 59 विद्यालय सीबीएसई और 44 विद्यालय यूपी बोर्ड से संबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के खाली पद भरने और विद्यार्थियों की शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में विभाग के मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और योजना की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि योजना 163 केंद्रों के माध्यम से संचालित है। इन केंद्रों पर 1783 इम्पैनल्ड शिक्षक हैं। यूपीएससी, पीसीएस, नीट, जेईई, एनडीए&एसीडीएस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 23801 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। सीएम ने कहा कि छात्रवृत्ति का लाभ प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को समय से मिलना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति से वंचित विद्यार्थियों के लिए आवेदन पोर्टल तत्काल खोला जाए और हर हाल में दो अक्टूबर तक छात्रवृत्ति की धनराशि अंतरित कर दी जाए।

वंदे मातरम के विरोध पर राजनाथ का कांग्रेस पर हमला, कहा- देशभक्ति पर उठता है सवाल

नई दिल्ली, (एजेंसी)।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम के सम्मान से औपचारिक रूप से इंकार करने और इसके विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण तथा संवैधानिक दृष्टि से गंभीर विषय बताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से इनकार करने पर देशभक्ति पर सवाल उठता है और संविधान के प्रति निष्ठा भी संदेह के घेरे में आ जाती है। राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो संदेश में कहा कि भारत के संविधान के अनुसार संसद देश की सर्वोच्च संस्था है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी होता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानून को मानने से इनकार करता है तो संविधान के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि कोई राष्ट्रगीत का सम्मान करने से मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान लग जाता है। उन्होंने कांग्रेस के वंदे मातरम को लेकर लिए गए निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे संवैधानिक और राजनीतिक दोनों दृष्टि से गंभीर बताया दरअसल, कांग्रेस ने वर्ष 1937 में पार्टी द्वारा पारित एक प्रस्ताव का हवाला देते हुए वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद ही गाने का निर्णय किया है। कांग्रेस का कहना है कि उस समय यह निर्णय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे शीर्ष नेताओं की सहमति से लिया गया था। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के 1937 के प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे झुककर पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा देश को आगे चलकर विभाजन के रूप में भुगतना पड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा कि कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना हमेशा देश के लिए घातक साबित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस भी कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है और यह देश के भविष्य के लिए गंभीर खतरे का संकेत है।

ओलंपिक 2036– केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा– टैलेंट स्काउटिंग पर फोकस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से देशव्यापी खेल प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा को आगे बढ़ाते हुए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को 2036 ओलंपिक के लिए भारत के एथलीट्स के मजबूत समूह को तैयार करने हेतु प्रतिभाओं की पहचान के लिए तेज और व्यापक कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) की 63वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि अगले दशक में भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार अभी से तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, "देश में ओलंपिक की मेजबानी से पहले के अगले 10 वर्षों की योजना पर अभी से जोर–शोर से काम शुरू करना होगा।" केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने कहा कि साई को अपने टैलेंट खोजने के सिस्टम को मजबूत करना चाहिए और ऐसे एथलीट्स की पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम बनाना चाहिए जिनमें उच्चतम स्तर तक आगे बढ़ने की क्षमता हो। उन्होंने कहा, "टैलेंट की पहचान दो अलग–अलग चरणों में होनी चाहिए। पहला, उन एथलीट्स की पहचान करना जो राज्य और जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर उन एथलीट्स की क्षमता का आकलन करने के लिए उनकी मैपिंग करना और यह तय करना कि क्या उनमें अगले स्तर तक आगे बढ़ने के लिए फिटनेस, जुनून, समर्पण और क्षमता है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा है कि टैलेंट की पहचान में स्कूलों, जिलों और कॉलेजों सहित पूरे स्पोर्ट्स पिरामिड को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "इसका मकसद एक व्यापक प्रतिभा भंडार बनाना होना चाहिए, जिसे बाद में स्पोर्ट्स स्कूलों और उच्च–स्तरीय ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़ा जा सके। उन्होंने ट्रेनिंग इकोसिस्टम का विस्तार करने के लिए पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ऐसे फ्रेमवर्क के तहत, राज्य और जिला–स्तरीय टैलेंट हंट के जरिए पहचाने गए ।

महिलाओं–युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर – सीएम

देहरादून, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत 'चौपाल–2026' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के सभी जिलों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला, युवा और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि श्मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजनाश के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया गया है। वहीं, आठ हजार से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता एवं आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के गांव अब प्रदेश के विकास में सहभागी बनने के साथ आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश के युवाओं और मातृशक्ति में हुनर और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, जबकि स्थानीय उत्पादों में देश–दुनिया के बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। जरूरत केवल हुनर को सही दिशा और बाजार उपलब्ध कराने की है। इसी सोच के साथ श्मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजनाश को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि योजना के तहत ग्रामीण उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने और उसका विस्तार करने के लिए प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ने में सहायता दी जा रही है।

महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर आपदा प्रबंधन योजना एवं टेबल टॉप अभ्यास से परखी गई आपातकालीन तैयारिया

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम पर आज आपदा प्रबंधन योजना एवं टेबल टॉप अभ्यास का सफल आयोजन किया गया।अभ्यास के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न विभागों एवं संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय, त्वरित सूचना–संचार, राहत एवं बचाव कार्य तथा चिकित्सा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की गई।हवाई अड्डे की आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं, विमान दुर्घटना एवं आगजनी जैसी मानव निर्मित घटनाओं तथा अन्य संभावित आपात स्थितियों को शामिल करते हुए एल–0 से एल–3 तक चार स्तरों में प्रतिक्रिया व्यवस्था निर्धारित की गई है।योजना के तहत हवाई अड्डे की वायु यातायात नियंत्रण सेवा (एटीसी), अग्निशमन सेवा एवं सीआईएसएफ के साथ जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की व्यवस्था की गई है।टेबल टॉप अभ्यास में आपातकालीन परिदृश्य का परीक्षण अभ्यास के दौरान एटीआर–72 विमान की आपातकालीन लैंडिंग एवं इंजन में आग की चेतावनी पर आधारित काल्पनिक परिदृश्य का परीक्षण किया गया। इस दौरान एटीसी द्वारा लगभग 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर संबंधित प्राथमिक राहत एवं बचाव एजेंसियों को सूचना देने की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।घटना स्थल पर घायलों की पहचान एवं पी–1, पी–2 एवं पी–3 श्रेणियों के अनुसार चिकित्सा वर्गीकरण (ट्राइएज), पैरामेडिकल टीम द्वारा टैगिंग, अलग–अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था तथा विमान के चालक दल के लिए पृथक व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई।आपात कालीन स्थिति में सभी संबंधित एजेंसियों के वाहनों एवं राहत दलों के त्वरित आवागमन के लिए गेट संख्या–1 के बाहर रेंडेवू प्वाइंट (आरवी प्वाइंट) चिन्हित किया गया है। समर्पित मोबाइल कमांड पोस्ट की व्यवस्था होने तक त्वरित कमांड एवं समन्वय के लिए इंडिगो की यात्री बस को अंतरिम मोबाइल कमांड पोस्ट के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया।अधिकारियों एवं स्टेकहोल्डर्स सहभागिता किया।टेबल टॉप अभ्यास के दौरान सभी संबंधित एजेंसियों ने अपने–अपने दायित्वों एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया की समीक्षा की तथा आवश्यक सुधारात्मक कदमों पर विचार–विमर्श किया।इस अवसर पर आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। इसके अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, आवश्यक बुनियादी ढांचे का उन्नयन तथा भविष्य में आधुनिक सिमुलेशन एवं तकनीकी प्रणालियों को अपनाने की दिशा में रोडमैप तैयार किया गया है।महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्याधाम यात्रियों की सुरक्षा, आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया तथा सभी संबंधित एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए निरंतर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है।इस अवसर पर प्रशासनिक/एफआर अमित भट्ट, एयरपोर्ट निदेशक धीरेंद्र सिंह, सीओ सिटी श्रेयाश त्रिपाठी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एम.पी. सिंह, एसडीआरएफ की टीम, एयरपोर्ट के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष (एचओडी) एवं विभिन्न संबंधित स्टेकहोल्डर्स उपस्थित रहे।

संपादकीय

रेलवे के बदहाल स्टेशन

रिपोर्ट इस सोच चुनौती देती है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण बुनियादी यात्री सेवाओं की गारंटी कर देता है। जहां स्टेशनों को फिर से बनाया गया, उनमें से भी कई जगहों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। रेलवे स्टेशनों की दुर्दशा वैसे तो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब उनकी बदहाली की विस्तृत तस्वीर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी सामने रखी है। गैर–उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं एवं स्वच्छता के हाल पर केंद्रित यह रिपोर्ट सभी 16 रेलवे जोनों के 512 ऐसे स्टेशनों के ऑडिट पर आधारित है। सीएजी ने स्टेशनों का चयन यात्रियों की आवाजाही और वहां से होने वाली कमाई को ध्यान में रखते हुए किया। उसने रेलवे डेटा, यात्री शिकायतों, यात्री प्रतिक्रियाओं, और रेलवे अधिकारियों के साथ मिल कर किए गए निरीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष है कि 89 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर एक या अधिक न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की कमी है। और समस्या केवल छोटे स्टेशनों पर ही नहीं, बल्कि बड़े, उच्च–राजस्व और अधिक यात्री आवाजाही वाले स्टेशनों पर भी उसी तरह मौजूद है। समस्या हैरू सुविधाओं का ना होना और जो सुविधाएं मौजूद हैं, उनकी नाकाफी क्षमता तथा उनका रखरखाव ठीक ना होना। रिपोर्ट के मुताबिक 188 स्टेशनों पर पेय जल के पर्याप्त नल उपलब्ध नहीं थे, जो रेल मंत्रालय के इस दावे का खंडन करता है कि ऐसी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। रिपोर्ट इस सोच चुनौती देती है कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण खुद ही बुनियादी यात्री सेवाओं की गारंटी कर देता है। यहां तक कि जहां स्टेशनों को फिर से बनाया गया है और जिन्हें बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेशन समझा जाता है, उनमें से भी कई जगहों पर यात्रियों को पानी, पंखे, बैठने की जगह, शौचालय, और स्वच्छता की कमी आदि का सामना करना पड़ रहा है। सार है कि भारतीय रेलवे के पास मानदंड, फंड और निगरानी के ढांचे तो मौजूद हैं, लेकिन उनके जरिए अमल असमान बना हुआ है। कारण जवाबदेही के सिस्टम का अभाव है। इस कारण सुविधाओं को मानदंडों के अनुसार प्रदान नहीं किया जाता, कार्यों के पूरा होने में देर होती है, मौजूद सुविधाओं का रखरखाव नहीं किया जाता, और कमियों को समयबद्ध कार्य योजनाओं के जरिए दूर नहीं किया जाता है। और इन सबको लेते हुए ही भारत विकसित होने की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है!

लूट सके सो लूट, हाँक सके सो हाँक

शंकर शरण

देश भर में हर शिक्षा संस्थान में प्रवेश, और वहाँ की परीक्षा, हर प्रश्न–पत्र, हर मूल्यांकन, आदि एक ही आफिस से करने का निर्णय लिया गया होगा। ऐसी मतिहीनता सामान्य बुद्धि से भी अटपटी लग सकती है। कि कहीं एक भी गड़बड़ी, एक भी भूल, एक की पतिताई, आदि कुछ भी देश भर के लाखों व्यक्तियों, संस्थाओं को कष्ट देगी। बार–बार परेशान करेगी।ज. कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईटन, हैरो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आदि सभी विख्यात शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सरकारी कार्यालय टेस्ट लेगा! ऐसा करना हर तरह से मूढ़ता पूर्ण है। पर यहाँ किया जा रहा है।

वरना, सोच कर बताएं कृ यह किस ने, और किस उद्देश्य से तय किया कि प्रवेश परीक्षा में शून्य अंक पाने वाला भी एक बड़े विश्वविद्यालय में पीएचडी करने के लिए प्रवेश पा सकता है? इस के उत्तर में बचाव में जितनी बातें होंगी, सब राजनीतिक और स्वार्थ, ईर्ष्या–द्वेष, लफ्फाजी का बवंडर होगा। उस में शिक्षा या ज्ञान के प्रति कोई चिंता या समझ भी लक्षित नहीं होगी। यही हैरू शिक्षा का गरीब की जोरू होना! इस पर हर कोई कुछ भी बोलने, करने, थोपने, फतवे देने का अधिकारी है। मानो, यही एक क्षेत्र है जिस के लिए किसी पात्रता की जरूरत नहीं! पार्टी कार्यकर्ता से लेकर ठेकेदार तक उस में अपनी चला सकते हैं। चलाते हैं। इसी दृष्टिकोण से देश भर में हर शिक्षा संस्थान में प्रवेश, और वहाँ की परीक्षा, हर प्रश्न–पत्र, हर मूल्यांकन, आदि एक ही आफिस से करने का निर्णय लिया गया होगा। ऐसी मतिहीनता सामान्य बुद्धि से भी अटपटी लग सकती है। कि कहीं एक भी गड़बड़ी, एक भी भूल, एक की पतिताई, आदि कुछ भी देश भर के लाखों व्यक्तियों, संस्थाओं को कष्ट देगी। बार–बार परेशान करेगी। जबकि स्थानीय, संस्थागत, राज्यवार, आदि क्षेत्राधिकार में स्वयं संपूर्ण रहने पर हर संस्था, हर परीक्षा, हर मूल्यांकन की गुणवत्ता अधिक सुरक्षित, स्पष्ट, सीमित, जिम्मेदार, और इसलिए उत्कृष्टता की संभावना भी बनी रहती है। यही पहले था भी। यूरोप और अमेरिका के शैक्षिक संस्थानों में अभी भी वही है। उच्च कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ईटन, हैरो, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, आदि सभी विख्यात शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक सरकारी कार्यालय टेस्ट लेगा! ऐसा करना हर तरह से मूढ़ता पूर्ण है। पर यहाँ किया जा रहा है। जो शिक्षा की गुणवत्ता और उत्कृष्टता को पेंदे में पहुँचा देने का अचूक उपाय है। मानो भारतीय विश्वविद्यालय रूपी फैक्ट्री से औसत कुली–कर्मचारी बनने लायक औसत माल तैयार करना हो। बस। इस से अधिक की कल्पना नहीं, चिन्ता नहीं। वैसे भी, हर चीज का श्केंद्रीकरणच्य एक कम्युनिस्ट–लोकतंत्री मानसिकता है। यह अंध–मानसिकता कि सब कुछ श्जनताच्य, यानी उस के नाम पर पार्टी करेगी। फिर पार्टी के नाम पर भी एक पार्टी–कमिटी, बल्कि उस का प्रमुख, यानी अंततरू एक नेता। क्या यह कृ एक देश एक परीक्षा कृ भी, श्एक देश एक चुनाच्य, श्एक देश एक पार्टीच्य, और श्एक देश एक नेताच्य की तरह की बे–सिर–पैर की कल्पना ही है? यह रूसी कम्युनिस्ट मानसिकता का ही भारतीय हिन्दू रूप जैसा है। परन्तु, इस तरह सब कुछ एक हाथ में केंद्रित कर देना बुद्धि, विवेक, जिम्मेदारी, और गुणवत्ता का सत्यानाश करने का ही प्रबंध करना है। पूरे सोवियत कम्युनिज्म के इतिहास का सबक और क्या है? पूरे सत्तर बरस, पूरा देश चुपचाप ऊपर का मुँह देखने, और ऊटपटाँग हुक्म मानने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था! साथ ही, जो भी गड़बड़ी हो रही हो, पहले उसे छिपाना, लीपा–पोती करना, और जब बात खुल जाए तो श्विदेशियोंच्य, श्गद्दारोंच्य, या श्कामचोरोंच्य को दोष देकर फिर वैसे ही उल्टा–सीधा करते जाना। यही दशकों से सोवियत कम्युनिज्म में चलता रहा। उसी कम्युनिज्म से स्वतंत्र भारत की अनेकानेक शासकीय नीतियाँ प्रभावित रही है। चूँकि उस से मुन्नी भर राजनीतिक वर्ग असीम शक्ति, सुविधा, और भोग–विलास का अवसर पाता रहा है। इसलिए भी हर चीज पर राजकीय कब्जा करने, फिर केंद्रीकरण, आदि उसी पार्टी–एकाधिकारी मानसिकता की व्युत्पत्ति है। सब पर हम, सब कुछ पर हमारा चले। सब हमारे ताबेदार। जो विरोध करें, वह जनता के दुश्मन, या विदेशी एजेंट। इस तरह की बनी–बनाई रट, यहाँ भी सोवियत यूनियन से ही मिलती जुलती लंबे समय से रही है। दशकों पहले कारखानों का, बैंकों का, अनेक उद्योग व्यापारों, आदि का राष्ट्रीयकरण उसी भावना में हुआ था। जब दशकों में भारी बर्बादी और लूट करके, साथ ही अंतहीन कुव्यवस्था से आगे चलना एकदम असंभव हो गया, तब जाकर किसी तरह कुछ बदलाव हुए। वह भी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की चतुराई से, लगभग चुपचाप, छिपाकर। पर यहाँ आम राजनीतिक वर्ग की वह एकाधिकारी, मनमानी, विशेषाधिकार, राजकीय संसाधनों की छीना–झपट, आदि की मानसिकता यथावत है। शिक्षा क्षेत्र उस का एक बड़ा उदाहरण है। अभी देश के विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों का आम नजारा है कृ श्लूट सके सो, लूट। हाँक सके सो बहरहाल, केंद्रीकरण करने वालों ने यह मोटी बात भी नहीं देखी कि सालो भर, नियमित रूप से, लाखों–लाख आवेदनों को जब एक केंद्रीय कार्यालय में देखा जाएगा।

नितिन नवीन की नई टीमः नई ऊर्जा और नया संतुलन

ललित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा के साथ यह संकेत दे दिया है कि भाजपा अब संगठन को केवल पदों के पुनर्विन्यास

के रूप में नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक दौर की आवश्यकताओं के अनुरूप नए सिरे से गढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। 17 अगस्त 2026 को घोषित नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महासचिव और 16 राष्ट्रीय सचिवों सहित संगठन के विभिन्न स्तरों पर व्यापक परिवर्तन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम को संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी जुड़ाव का मिश्रण बताया है। इस टीम को समझने के लिए इसे केवल 'कौन आया और कौन गया' के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे भाजपा की दीर्घकालीन संगठनात्मक रणनीति, सामाजिक समीकरणों की समझ और आने वाले चुनावों की राजनीतिक चुनौतियों को पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन की टीम का सबसे बड़ा संदेश है–अनुभव को हटाकर युवा ऊर्जा नहीं लाई गई है, बल्कि अनुभव के साथ नई ऊर्जा को जोड़ा गया है। यही संतुलन किसी बड़े राजनीतिक संगठन को गतिशील बनाता है। राम माधव की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में वापसी इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगठन, वैचारिक संवाद और रणनीतिक राजनीति की उनकी समझ भाजपा के लिए उपयोगी हो सकती है। वसुंधरा राजे सिंधिया, डी. पुरंदेश्वरी, बैजयंत पांडा, तीरथ सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर यह स्पष्ट किया गया है कि नितिन नवीन ने वरिष्ठता और अनुभव को किनारे नहीं किया है। यह उस संगठनात्मक सोच का प्रमाण है जिसमें पुराने अनुभव को नई परिस्थितियों के अनुरूप इस्तेमाल करने की कोशिश दिखाई देती है। दूसरी ओर स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी देना भी केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं है। स्मृति ईरानी का राजनीतिक व्यक्तित्व आक्रामक संवाद, महिला मतदाताओं से जुड़ाव और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी राजनीतिक संप्रेषण से जुड़ा रहा है। उनकी वापसी भाजपा के लिए राजनीतिक संदेश और संगठनात्मक उपयोगिता–दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। उनके साथ विनोद तावड़े, सुनील बंसल जैसे संगठनात्मक अनुभव रखने वाले नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी मिलना संगठन और चुनावी प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल की ओर संकेत करता है। पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया जाना भी उल्लेखनीय है। यह जिम्मेदारी बताती है कि संगठन में राजनीतिक अनुभव के साथ प्रशासनिक, आर्थिक और पेशेवर दक्षता को भी महत्व दिया जा रहा है। बी. एल. संतोष का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने रहना संगठन की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अर्थात् नितिन नवीन ने पूरी तरह से 'पुराना हटाओ, नया लाओ' की नीति नहीं अपनाई, बल्कि जहां निरंतरता आवश्यक थी वहां उसे बनाए रखते हुए परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह बनाई है। नई टीम का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। भाजपा के लिए अब राजनीति केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, समाज के अलग–अलग वर्गों में संगठन की स्वीकार्यता और पहुंच बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नई टीम में महिलाओं, विभिन्न सामाजिक समुदायों, उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत तक के प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया है। रिपोर्टों के अनुसार टीम में महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को भी उल्लेखनीय जगह मिली है। यहां एक और महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है–भाजपा अब केवल अपने परंपरागत समर्थक वर्ग से संवाद करने के बजाय नए मतदाता समूहों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। युवा, प्रथम बार मतदान करने वाली पीढ़ी, शहरी पेशेवर, तकनीक से जुड़े वर्ग और महिलाओं की राजनीतिक आकांक्षाएं आज चुनावी परिणामों को प्रभावित करती हैं। इसलिए संगठन में ऐसे चेहरों की आवश्यकता है जो केवल राजनीतिक भाषण न दें, बल्कि बदलते समाज की भाषा समझें। भाजपा की नई टीम में इस दिशा का प्रयास स्पष्ट दिखाई देता है। विशेष रूप से युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के स्तर पर किए गए बदलाव इस बात का संकेत हैं कि संगठन भविष्य के मतदाता को आज से ही संबोधित करना चाहता है। जेन–जी को केवल सोशल मीडिया की पीढ़ी मानना भूल होगी। यह पीढ़ी रोजगार, तकनीक, उद्यमिता, पारदर्शिता, राष्ट्रवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अवसरों को लेकर अलग तरह की अपेक्षाएं रखती है। भाजपा यदि इस पीढ़ी से वास्तविक संवाद स्थापित कर पाती है तो उसका लाभ केवल आगामी चुनाव में नहीं, बल्कि 2030 और 2040 के दशक की राजनीति में भी मिल सकता है। नई टीम का सबसे बड़ा राजनीतिक परीक्षण हालांकि उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में होगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन की मजबूती का सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ता है। आगामी चुनावों की दृष्टि से भाजपा के सामने केवल सत्ता विरोधी भावनाओं का मुकाबला करने की चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष के बदलते गठजोड़, जातीय समीकरण, युवाओं की आकांक्षाओं और स्थानीय मुद्दों को भी साधना है। इसलिए राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना चुनावी दृष्टि से स्वाभाविक रणनीति है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि नई टीम का उद्देश्य केवल 2026–27 के चुनाव नहीं हो सकते। भाजपा की दृष्टि निश्चित रूप से 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे आगे तक जाती है। 'विकसित भारत 2047' का लक्ष्य तभी राजनीतिक और सामाजिक आधार प्राप्त कर सकता है जब पार्टी संगठन निरंतर नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ता रहे। इसलिए नितिन नवीन की टीम को एक प्रकार से 2029 की तैयारी और 2047 की राजनीतिक–संगठनात्मक नींव के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के स्तर पर भी आने वाले समय में परिवर्तन या विस्तार की अटकलें स्वाभाविक हैं, विशेषकर जब सरकार को आगामी राज्यों के राजनीतिक समीकरणों और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को साथ लेकर चलना है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में अभी किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जैसे अनुभवी नेताओं के संभावित भविष्य की चर्चा राजनीतिक हलकों में हो सकती है, पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व पर निर्भर करेगा। नरेन्द्र मोदी की राजनीति में संगठन और सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों के माध्यम से ऊर्जा पैदा करने की परंपरा रही है।

मौत की सजा बरकरार, लेकिन पूरी तरह खुला है इसे खत्म करने का रास्ता

के रवींद्रन

अदालत ने मौत की सजा देने के राज्य के मौजूदा तरीके को सही ठहराया है, साथ ही यह भी माना है कि उस तरीके का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक आधार पुराने पड़ सकते हैं। एक बार जब यह समझा जाता है कि संवैधानिक वैधता बेहतर जानकारी के अनुसार बदल सकती है, तो मौत की सजा की बड़ी संस्था भी तार्किक रूप से उसी जांच–परख से अछूती नहीं रह सकती। यहीं पर मौत की सजा के विरोधियों को सही मायने में उम्मीद मिल सकती है। यह फैच्सला मौत की सजा को खत्म नहीं करता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी देकर मौत की सजा देने को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी संविधान पीठ को भेजने से इन्कार करना, पहली नजर में मौत की सजा की कानूनी नींव को मजबूत करने जैसा लग सकता है। परन्तु करीब से देखने पर यह ज्यादा मुश्किल दिशा की ओर इशारा करता है। बेंच ने मौजूदा कानून को तो बचाए रखा है, लेकिन जानबूझ कर इसे वैज्ञानिक या संवैधानिक रूप से नहीं बदलने लायक मानने से इन्कार कर दिया है। यह मानकर कि औषधि विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान (मस्तिष्क विज्ञान), और प्रत्यक्ष शोध में तरक्की पहले के फैसले के पीछे की सोच को बदल सकती है, इसने एक ऐसी बहस में एक जरूरी रास्ता खोला है जो फांसी की यांत्रिकी से कहीं आगे तक जाती है।न्यायालय के सामने मामला तकनीकी रूप से फांसी देने के तरीके के बारे में था, न कि मौत की सजा की संवैधानिक वैधता के बारे में। याचिका में फांसी को बेवजह दर्दनाक बताते हुए चुनौती दी गई थी और मृत्युकारक इंजेक्शन जैसे विकल्पों पर विचार करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति द्वय विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ को पहले के न्यायिक फैसले को फिर से खोलने के लिए काफी कारण नहीं मिले कि फांसी संवैधानिक जरूरतों को पूरा करती है। फिर भी, इस सवाल को हमेशा के लिए बंद करने से इन्कार करना खुद खारिज करने से ज्यादा जरूरी साबित हो सकता है। न्यायालय ने साफ तौर पर भविष्य में जांच करने पर विचार किया अगर मजबूत वैज्ञानिक, चिकित्सकीय या प्रत्यक्ष प्रमाण यह दिखाता है कि मौजूदा प्रणाली को बल देने वाले तथ्य का आधार काफी बदल गया है।इस योग्यता पर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि संवैधानिक फैसले को हमेशा मनुष्य के ज्ञान में हुई तरक्की से अलग नहीं किया जा सकता। चार दशक पहले स्वीकार्य मानी जाने वाली प्रक्रिया चिकित्सकीय समझ में सुधार के बाद बहुत अलग लग सकती है। चेतना, दर्द, तंत्रिकाजन्य परेशानी और मरने की प्रक्रिया के बारे में विज्ञान जो साबित करता है, वह इस संवैधानिक आकलन को बदल सकता है कि सजा क्रूर, अपमानजनक या मनुष्य की गरिमा के साथ मेल खाती है या नहीं। लेकिन एक बार जब यह बात मान ली जाती है, तो एक जरूरी सवाल उठता है। वैज्ञानिक जांच सिर्फ यह तय करने पर क्यों रुकनी चाहिए कि राज्य कैसे मारता है? यह समान रूप से यह भी जांच सकता है कि पारंपरिक रूप से मौत की सजा को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मकसद असल में मारने से पूरे होते हैं या नहीं। भारतीय संवैधानिक स्थिति श्दुर्लभों में दुर्लभतमश मामलों में मौत की सजा की इजाजत देती है, जिसमें उम्रकैद को सामान्य विकल्प माना जाता है। इस नियम का मकसद फांसी को खास बनाना था। हालांकि, दशकों से, न्यायपालिका को खुद यह तय करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है कि क्या पर्याप्त माना जाएगा। अलग–अलग न्यायाधीश क्रूरता, हालात कम करने, सुधार की संभावना, सामाजिक पृष्ठभूमि और दूसरे कारकों को अलग–अलग तरह से तौल सकते हैं। मौत का ऐसा स्वभाव जिसे बदला न जा सके, ऐसे हर बदलाव को खास संवैधानिक नतीजे का मामला बना देता है।यहीं पर मौत की सजा पर नैतिक आपत्ति कानूनी बहस से जुड़ती है। यह बात कि एक इंसान को दूसरे इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए, आधुनिक संवैधानिक कानून से कहीं ज्यादा पुरानी नैतिक और आध्यात्मिक परंपराओं से निकली है। मानने वालों के लिए, जिंदगी पर अधिकार आखिरकार भगवान का हो सकता है। एक धर्मनिरपेक्ष सूत्रीकरण भी इसी उलझन में अलग तरह से पहुंचता हैरू राज्य, जो त्रुटिपूर्ण इंसानी संस्थाओं से बना है, एक खास ताकत तब हासिल कर लेता है जब वह जानबूझ कर किसी ऐसी जिंदगी को खत्म कर देता है जिसे वह पहले से ही कैद और अक्षम कर सकता है। मौत की सजा को बनाए रखने के लिए सबसे मजबूत तर्क हमेशा यह रहा है कि कुछ अपराध इतने भयानक होते हैं कि कोई भी कम सजा उनकी गंभीरता को ठीक से नहीं दिखा सकती। हत्या के शिकार लोगों के परिवार जाहिर तौर पर न्याय की मांग करते हैं, और आतंकवाद, हत्या के साथ यौन हिंसा या बहुत ज्यादा क्रूर हत्याओं का सामना कर रहे समाज उस मांग को सिर्फ बदला कहकर खारिज नहीं कर सकते। एक संवैधानिक लोकतंत्र को पीड़ितों और जन सुरक्षा को गंभीरता से लेना चाहिए। फिर भी न्याय और फांसी एक जैसे नहीं हैं। भारतीय कानून में समाज की रक्षा करने में सक्षम सजा के विकल्प तेजी से बढ़ रहे हैं, बिना राज्य को मारने की जरूरत के। सर्वोच्च न्यायालय ने सही हालात में दोषी की बाकी जिंदगी के लिए जेल की सजा को बढ़ाने की वैधता की फिर से पुष्टि की है। ऐसी सजाएं इस तर्क को बहुत कमजोर

कर देती हैं कि फांसी जरूरी है क्योंकि खतरनाक अपराधी जल्दी से समाज में लौट सकते हैं। ज्यादा मुश्किल वजह रोकथाम है। मौत की सजा अक्सर इस सहज आकर्षक सोच पर आधारित रही है कि मौत का डर संभावित हत्यारों को जेल से ज्यादा असरदार तरीके से हतोत्साहित करेगा। लेकिन सहज ज्ञान वैज्ञानिक सुबूत नहीं है। अपराध अक्सर गुस्से, हताशा, विचारधारा, नशे, मानसिक परेशानी या ऐसे हालात से होता है जिनमें अपराधी संभावित सजा की तुलनात्मक गंभीरता का सही अंदाजा नहीं लगा पाते हैं। अगर पक्के सुबूत यह साबित नहीं कर पाते कि फांसी, लंबी जेल की तुलना में हत्या को ज्यादा असरदार तरीके से रोकती है, मौत की सजा के पक्ष में दिए जाने वाले मुख्य व्यावहारिक तर्कों में से एक काफी कमजोर पड़ जाता है। न्यायिक गलती की संभावना भी होती है। आपराधिक न्याय प्रणाली जांचकर्ताओं, गवाहों, फोरेंसिक सुबूतों, सरकारी वकीलों, बचाव पक्ष के वकीलों और जजों के जरिए काम करती है। इन सभी हिस्सों में इंसानी फैसले शामिल होते हैं। अदालतें गलत सजा को सुधार सकती हैं क्योंकि कैदी जिंदा रहता है। गलत तरीके से दी गई मौत की सजा में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए, सजा जितनी ज्यादा अपरिवर्तनीय होती है, संस्थागत निश्चितता का मानक उतना ही मजबूत होना चाहिए। भारत में मौत की सजा से जुड़े कानूनी नजरिए में इस समस्या को लेकर बढ़ती चिंता दिखती है। ऊपरी अदालतों ने बार–बार यह जांचा है कि क्या निचली अदालतों ने मौत की सजा सुनाने से पहले नरमी बरतने लायक हालात और सुधरने की संभावना पर ठीक से विचार किया था।

जंगल की लड़ाई शहरों तक पहुंचेगी

अजीत द्विवेदी

पिछले कुछ वर्षों से एक परिघटना के तौर पर श्अर्बन नक्सलच्य की चर्चा हो रही है। बड़े शहरों खास कर महानगरों में रहने वाले कुछ बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार भी किया गया। उनके ऊपर नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप लगे। भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने के प्रयास के आरोपों में जांच हुई और कई बौद्धिकों के कंप्यूटर से कथित तौर पर हिंसा को समर्थन देने वाले दस्तावेज व चिट्ठियां बरामद हुईं। इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए फादर स्टेन स्वामी का न्यायिक हिरासत में निधन हो गया। उनके हाथ कांपते थे और उनको पानी पीने के लिए स्ट्रॉ चाहिए था तो उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। सरकार उनके प्रति इतनी सख्त थी कि जेल प्रशासन स्ट्रॉ तक नहीं दे रहा था। गौतम नवलखा से लेकर आनंद तेलतुम्बडे और प्रोफेसर जी साईबाबा तक अनेक लोग गिरफ्तार हुए और लंबे समय तक जेल में रहे। अब प्रधानमंत्री ने श्दिमागी नक्सलच्य का एक नया जुमला ईजाद किया है। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से अपने 13वें भाषण में यह जुमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जंगल के नक्सलियों, जिनके लिए उन्होंने श्हथियारी नक्सलच्य शब्द का इस्तेमाल किया, का सफाया हो चुका है। इसके बाद उन्होंने श्दिमागी नक्सलच्य की पहचान करने और उन्हें समाप्त करने का आह्वान किया। यह श्अर्बन नक्सलच्य से आगे की परिघटना है। ऐसा लग रहा है कि श्अर्बन नक्सलच्य का विमर्श वांछित परिणाम नहीं दे सका है। शहरी और ग्रामीण विभाजन में यह मामला कहीं खो गया। मध्य वर्ग के कुछ लोगों को एक अवधारणा के तौर पर यह अच्छा लगा लेकिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई उनमें से ज्यादातर को सामान्य लोग नहीं जानते थे या उनसे कनेक्ट नहीं कर सके। इसलिए उनके लिए ऐसे लोगों को खतरे के तौर पर देखना थोड़ा मुश्किल था। तभी ऐसा लग रहा है कि उससे आगे की परिघटना के तौर पर श्दिमागी नक्सलच्य का विचार प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे अलग से परिभाषित नहीं किया लेकिन जिस तरह उन्होंने श्हथियारी नक्सलच्य के बरक्स श्दिमागी नक्सलच्य को रखा उससे परिभाषा बहुत स्पष्ट है। इसका पहला उद्देश्य तो यह दिख रहा है कि श्अर्बन नक्सलच्य से जो बात ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची उसे श्दिमागी नक्सलच्य के नाम पर पहुंचाया जाए। दूसरा मकसद यह दिख रहा है कि इसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र की बजाय अखिल भारतीय परिघटना बनाया जाए। तीसरा उद्देश्य जंगल की लड़ाई को घर घर में और गली गली में पहुंचाना है। ध्यान रहे लोग नक्सल का एक ही मतलब समझते हैं। जिनको इसका इतिहास, भूगोल भी नहीं पता है वे भी मानते हैं कि नक्सली वो लोग होते हैं, जो सरकार से लड़ते हैं और सुरक्षाकर्मियों पर हमला करते हैं। यह बहुत सरलीकृत धारणा है लेकिन आम भारतीय के मन में नक्सली की यही छवि है। यह बात खासतौर से उन इलाकों के लिए कही जा सकती है, जहां नक्सलवाद का असर नहीं रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, जहां माओवाद या नक्सलवाद का असर रहा उन राज्यों के बाहर इसके बारे में कोई स्पष्ट धारणा लोगों के मन में नहीं है। असर वाले राज्यों में भी शहरी इलाकों में लोग इससे अप्रभावित रहे हैं। तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में इनके प्रति सहानुभूति रखने और इन्हें समर्थन देने वाला भी एक बड़ा तबका हमेशा मौजूद रहा है। बहरहाल, जो बिल्कुल ही अप्रभावित रहे या नक्सलवाद की परिघटना के भौगोलिक दायरे से बाहर रहे उनके मन में नक्सलियों को लेकर जो धारणा है वह सरकार विरोधी और सुरक्षा बलों पर हमला करने वालों के रूप में है। वे श्दिमागी नक्सलच्य को भी इसी रूप में देखेंगे। उनके लिए श्दिमागी नक्सलच्य वह है, जो सरकार का विरोध कर रहा है। भले विरोध लोकतांत्रिक हो। विरोध के तरीकों के आधार पर फर्क नहीं किया जाएगा। सशस्त्र विरोध और लोकतांत्रिक विरोध एक माने जाएंगे। तभी यह संभव है कि एक बरसात में धंस जाने वाले एक्सप्रेसवे का मुद्दा उठाने वाला श्दिमागी नक्सलच्य मान लिया जाए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का विरोध वाले से लेकर छात्र आंदोलन का समर्थन करने वालों को भी श्दिमागी नक्सलच्य ठहराया जा सकता है। सरकार की आर्थिक व विदेश नीति पर सवाल उठाने वाला या सुरक्षा बलों की कार्रवाई का विरोध करने वाला तो निश्चित रूप से श्दिमागी नक्सलच्य माना जाएगा। भारत या किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करने वालों का बचाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति मौजूदा व्यवस्था का विरोध करता है, नागरिक सुविधाओं की अनुपस्थिति की ओर ध्यान दिलाता है, सरकार से लेकर देश की अन्य संस्थाओं की साख पर सवाल उठाता है और उन्हें विश्वसनीय नहीं मानता है, उन्हें बदलने की बात करता है तो उसे श्दिमागी नक्सलच्य कहा जा सकता है? ध्यान रहे ऐसे ही लोगों को श्अर्बन नक्सलच्य कहा गया था। देश के बौद्धिकों को श्अर्बन नक्सलच्य कहा गया। किसान आंदोलन करने वालों को खालिस्तानी और उस आंदोलन का समर्थन करने वालों को श्अर्बन नक्सलच्य कहा गया। कोरोना के समय सरकार की हैंडलिंग पर सवाल उठाने वालों को श्अर्बन नक्सलच्य कहा गया। गरीब, आदिवासी और कश्मीरियों की लड़ाई लड़ने वाले ज्यादा निशाने पर रहे। मेधा पाटकर से लेकर अरुंधति रॉय तक सब श्अर्बन नक्सलच्य हैं। सामाजिक संगठनों पर पिछले कुछ वर्षों में जो कार्रवाई हुई है और विदेशी चंदे के लिए बने कानून, एफसीआरए के नियम सख्त करके गैर सरकारी संगठनों की फंडिंग रोकने का जो अभियान चला है उसके पीछे एक मुख्य कारण कथित श्अर्बन नक्सलच्य को कमजोर करना है। देश की कई प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थाओं को श्अर्बन नक्सलच्य से जोड़ा गया। अब इसे अमूर्त अवधारणा से निकाल कर व्यापक रूप से जनता के बीच ले जाने के लिए श्दिमागी नक्सलच्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कह सकते हैं कि एक चरण पूरा हो गया है और इस बार लाल किले से अगले चरण की घोषणा हुई है। असल में पिछले 12 साल से सरकार और भाजपा का विरोध करने वाले लोगों के लिए अलग अलग विशेषण गढ़े जा रहे हैं और उन्हें एक खांचे में फिट करने का प्रयास किया जा रहा है। कभी उनको श्खान मार्केट गैंगच्य कहा जाता है, श्कभी टुकड़े टुकड़े गैंगच्य कहा जाता है, कभी श्अर्बन नक्सलच्य कहा जाता है तो अब श्दिमागी नक्सलच्य कहा जाएगा। यहां एक पैटर्न साफ साफ दिखता है। देश के सम्भ्रांत वर्ग के साथ साथ ऐसे बौद्धिकों को निशाना बनाना है, जो सरकार की क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति पर सवाल उठाते हैं और उसकी विभाजनकारी नीतियों का विरोध करते हैं। ये दोनों सरकार की दुखती रग हैं। इनका विरोध करने वाले के लिए प्रयोग होने वाले विशेषण में नक्सली शब्द जोड़ दिया जाए तो यकीन दिलाना आसान हो जाएगा।

किसानों का प्रदर्शन मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल पर शुक्रवार 1 बजे भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शैलेश वर्मा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौपा है। जिलाध्यक्ष शैलेश वर्मा ने बताया कि किसानों को धान की फसल की सिंचाई के लिए समय पर नहर का पानी और बिजली उपलब्ध कराना शामिल है। साथ ही, सभी साधान सहकारी समितियों में किसानों के लिए आवश्यक खाद की उपलब्धता

सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अन्य मांगों में जिले के सभी नालों की सफाई, सभी ग्राम पंचायतों में आवारा पशुओं को गोशालाओं में पहुंचाना, और किसानों को 3 हॉर्स पावर तक मुफ्त बिजली प्रदान करना शामिल है।किसान ट्रैक्टर और डीजल इंजन के लिए डीजल पर छूट देने, ग्राम पंचायतों में मिट्टी की जांच कराने, और जिले की सभी सड़कों की मरम्मत कराने की भी मांग कर रहे हैं।इसके अतिरिक्त, किसानों का उत्पीड़न बंद करने, जौनपुर जिले में चीनी मिल की स्थापना करने, और ग्राम सभाओं में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा की गई सरकारी जमीन, खलिहान और बंजर भूमि को चिन्हित कर खाली कराने की मांग भी उठाई गई है।मांग पत्र में जौनपुर जिले में स्वच्छ जल योजना के तहत लगे 10:खराब ट्यूबवेलों को सही करने का मुद्दा भी शामिल है, जिनसे पानी नहीं आता है।

आरटीओ असॅफिस में रजिस्ट्रेशन के नाम पर धनउगाही के मामले में वाहन मालिकों ने किया प्रदर्शन बाबू के खिलाफ कार्रवाई की माग ब्यूरो प्रमुख

विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर के आरटीओ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के नाम पर कथित धनउगाही का मामला सामने आया है। शुक्रवार को एक ट्रक मालिक ने आरटीओ कार्यालय के गेट पर अपनी पांच गाड़ियां खड़ी कर डेढ़ घंटे तक प्रदर्शन किया। मड़ियाहूं निवासी ट्रक मालिक विनय कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि आरटीओ कार्यालय में तैनात बाबू गणेश मिश्रा उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति गाड़ी 10 हजार रुपये, यानी कुल 50 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। सिंह के अनुसार, उनकी गाड़ियां चार दिनों से आरटीओ में खड़ी हैं। आरटीओ के आरआई ने गाड़ियों की माप कर उन्हें श्ओकेश कर दिया था, लेकिन बाबू गणेश मिश्रा ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई। विनय कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने 3 करोड़ रुपये की पांच ट्रेलर गाड़ियां खरीदी हैं और रजिस्ट्रेशन में देरी के कारण उन्हें किश्त का नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसी तरह की समस्याओं के कारण जौनपुर की कई गाड़ियां बिहार में पंजीकृत हो रही हैं। सिंह ने कहा, ष्जो टैक्स लगेगा उसके अलावा 50 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो हमारी किश्त का नुकसान हो रहा है।ष उन्होंने यह भी बताया कि आरआई ने उनकी बात सुनी थी, लेकिन बाबू ने उनकी बात नहीं मानी। इस मामले पर आरआई अशोक यादव ने बताया कि बाबू गणेश मिश्रा हाईकोर्ट गए हुए हैं। उनके स्थान पर दूसरे बाबू को नामित कर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि प्रदर्शन के बाद गाड़ियों को हटवा दिया गया है और पैसे मांगने वाले बाबू की जांच की जाएगी।

सावन महोत्सव में झूले का रॉड गिरने से दो नाबालिग बालिकाएं घायल

लखनऊ, (संवाददाता)। थाना गाजीपुर क्षेत्र में आयोजित सावन महोत्सव के दौरान झूले पर बैठी दो नाबालिग बालिकाएं झूले का रॉड ऊपर से गिरने के कारण घायल हो गईं। घटना की सूचना 18 अगस्त 2026 को करीब रात 8 बजे थाना गाजीपुर पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।प्रारंभिक जांच के अनुसार 16 वर्ष और 14 वर्ष की दोनों नाबालिग बालिकाएं अपनी सहेलियों के साथ सावन महोत्सव में आई थीं। इसी दौरान झूले का एक रॉड अचानक ऊपर से गिर गया, जिसकी चपेट में आने से नीचे बैठी दोनों बालिकाओं को चोटें आईं।घटना के बाद दोनों बालिकाओं को तत्काल उपचार के लिए सुषमा अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों के हाथ और पैर में चोटें आई हैं। दोनों बालिकाओं के परिजन मौके पर मौजूद हैं और उनका उपचार जारी है।पुलिस के अनुसार दोनों बालिकाओं की हालत सामान्य है। घटना के बाद मौके पर शांति एवं कानून–व्यवस्था कायम है। पुलिस द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है।

चार थाना क्षेत्रों के पांच दबंगों पर कार्रवाई, छह माह के लिए जिला बदर

लखनऊ, (संवाददाता)। लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार थाना क्षेत्रों के पांच मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम–1970 के तहत गुंडा घोषित कर छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ के न्यायालय द्वारा की गई है।पुलिस के अनुसार गोसाईगंज, कृष्णानगर, बंथरा और मोहनलालगंज थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों और लोक शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम–1970 की धारा–3 के तहत न्यायालय में कार्रवाई की गई। सुनवाई के बाद संबंधित व्यक्तियों को गुंडा घोषित करते हुए छह–छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर किए गए लोगों में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सूरज मिश्रा (28 वर्ष), पुत्र लालजी मिश्रा, निवासी मातनटोला, चतुर्भुजी मंदिर के पास, कस्बा एवं थाना गोसाईगंज शामिल हैं।इसी क्रम में कृष्णानगर थाना क्षेत्र के सर्वेश पाल (21 वर्ष), पुत्र श्यामलाल पाल, निवासी 551कध480, संजय गांधी मार्ग, गली नंबर–4, आजादनगर तथा वीर सिंह (21 वर्ष), पुत्र राजकुमार यादव, निवासी अलीनगर सुनहरा को भी छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।बंथरा थाना क्षेत्र के अंकित राज उर्फ अंकित गौतम (31 वर्ष), पुत्र दिलीप कुमार, निवासी ग्राम बंथरा सिकंदरपुर को भी छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित किया गया है।वहीं मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र (45 वर्ष), पुत्र नन्हकऊ प्रसाद उर्फ नन्हकऊ, निवासी ग्राम केसरीखेड़ा, मजरा सिसेंडी को भी छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य ऐसे मनबढ़ और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा क्षेत्र में भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है।

जौनपुर में 10 सितंबर को निकलेगा बारावफात जुलूस

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर में रहमानिया सीरत कमेटी के अध्यक्ष सफीक रजा जौनपुरी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओ ने शुक्रवार को 11:30 बजे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को विभिन्न मांगों को लेकर एक पत्र सौपा है। अध्यक्ष सफीक रजा ने बताया कि शहर में 10 सितंबर , ग को बारावफात का जुलूस निकाला जाएगा। यह आयोजन 11 सितंबर तक चलेगा, जिसमें जश्ने ईद मिलादुन्नबी (स. अ.व.) मनाया जाएगा। जुलूस शाम 5 बजे शाही बड़ी मस्जिद पर एकत्रित होकर शुरू होगा। यह मल्हनी पड़ाव होते हुए रौजा कदम रसूल पहुंचेगा, जहां यह जलसे का रूप ले लेगा। इसमें शहर की अंजुमनें और फनसिपहगिरी के अखाड़े शामिल होंगे। जुलूस के पारंपरिक मार्गों पर विभिन्न समाजसेवी संगठनों द्वारा स्टॉल और स्टेज लगाए जाएंगे। इन स्थानों पर अंजुमनें कलाम पेश करेंगी और अखाड़े अपने फन का प्रदर्शन करेंगे। इन मार्गों को विभिन्न सजावट कमेटियों द्वारा सजाया जाएगा। दूसरे दिन, 11 सितंबर की शाम से रात्रि तक, अंजुमनें जलसे में अपना नातिया कलाम पेश करेंगी, जिसके बाद कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। आयोजन

के लिए कई व्यवस्थाओं की मांग की गई है। इनमें शाही बड़ी मस्जिद से जुलूस के पारंपरिक मार्ग पर गड्ढा मुक्त सड़कें सुनिश्चित करना, मार्गों पर साफ–सफाई और चूना छिड़काव कराना शामिल है। संबंधित विभागों को आवारा पशुओं और सूअरों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। विद्युत आपूर्ति के लिए 10 और 11 सितंबर को पूर्व की भांति 7.5 केवी के पांच जनरेटर डीजल सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी मस्जिद और पुरानी बाजार चौकी के पास दो मोबाइल शौचालय की व्यवस्था भी मांगी गई है। सुरक्षा और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। 10 सितंबर को शाम 4 बजे से जुलूस और जलसे के मार्गों पर वाहन और ई–रिक्शा के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त, 10 और 11 सितंबर को अग्निशमन इकाई (वाहन सहित), एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप की तैनाती की जाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में सैकड़ों वकील न्यायिक कार्य से विरत रहे

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में शुक्रवार सुबह अधिवक्ताओं ने उच्च न्यायालय के एक आदेश के विरोध में न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष घनश्याम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों वकील इस विरोधा प्रदर्शन में शामिल हुए।

अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रमण करते हुए जमकर नारेबाजी की और उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस संबंध में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन जौनपुर की एक आवश्यक बैठक संघ के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष घनश्याम सिंह एडवोकेट ने की, जबकि संचालन संयुक्त मंत्री हीरामणि यादव एडवोकेट ने किया। इसमें अधिवक्ता राम आसरे

दूबे और अरुण कुमार श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व महामंत्री ओम प्रकाश सिंह एडवोकेट और आनंद कुमार मिश्र एडवोकेट सहित उमाशंकर तिवारी, राम आसरे यादव और यशवंत यादव जैसे कई अन्य सम्मानित अधिवक्ताओं ने भी अपनी बात रखी। अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट और बार काउंसिल द्वारा हड़ताल पर रोक लगाने तथा बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दों पर भी चिंता व्यक्त की। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि माननीय जिलाधिकारी जौनपुर, चकबंदी न्यायालय कटारा जौनपुर, उपभोक्ता फोरम जौनपुर और समस्त न्यायालयों को सूचनार्थ प्रेषित की जाएगी।

श्रावस्ती एनकाउंटर पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पिछले साल मई में हुए एक पुलिस एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पुलिस की कहानी पर गंभीर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस की एफआईआर में कई विरोधाभास साफ नजर आ रहे हैं और संबंधित थानाध्यक्ष ने घटना का झूठा विवरण पेश किया प्रतीत होता है, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपी छोटकऊ उर्फ अलाउद्दीन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। पीठ ने कोर्ट ने सीबीआई को तीन महीने के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है, साथ ही श्रावस्ती सत्र अदालत में अलाउद्दीन के खिलाफ चल रही अदालती कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। एफआईआर के अनुसार, 9 मई, 2025 को अलाउद्दीन के खिलाफ 7 वर्षीय बच्चे के अपहरण

के आरोप में इकौना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 12 मई, 2025 को तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे ने एक और एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि आरोपी अलाउद्दीन नेपाल भागने की फिराक में था। अलाउद्दीन पर इकौना थाने के तत्कालीन एसएचओ अश्विनी कुमार दुबे ने आत्मरक्षा में दो गोलियां चलाई थीं, जो सीधे उसके दोनों पैरों में लगीं। एसएचओ का दावा था कि उन्होंने रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर 15 मीटर दूर से अपनी 9 एमएम सर्विस पिस्टल से सटीक फायर किया था। हाईकोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि एक ही वाहन में सवार 23 पुलिसकर्मियों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ।

नगर निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं की महापौर ने की समीक्षा

लखनऊ, (संवाददाता)।महापौर सुषमा खर्कवाल ने बुधवार को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ बैठक कर निर्माण कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा नगर निगम लखनऊ के लिए कराई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में महापौर ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने निर्माणाधीन नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और मौके पर चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।बैठक में महापौर ने सीएनडीएस द्वारा कराई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण की गति तथा कार्यों में आ रही बाधाओं के बारे में अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गति धीमी है, उनमें तत्काल तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कार्य गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर पूरे किए जाएं।समीक्षा बैठक में नगर निगम लखनऊ के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण, अमौसी में मैंगो पार्क, किला मोहम्मदी नाला के रीमॉडलिंग एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आलमबाग से हैदर कैनाल तक गीतापल्ली नाले के डायवर्जन के लिए आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण तथा विभिन्न पंपिंग स्टेशनों पर बाढ़ पंपिंग एवं जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।इसके अलावा औरंगाबाद में वर्किंग वूमेन हॉस्टल, साहित्य पार्क तथा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना 2025–26 के अंतर्गत जोन–7 में जोनल कार्यालय के निर्माण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। महानगर क्षेत्र में कुकरैल नदी के किनारे अयोध्या मार्ग स्थित नगर निगम की भूमि पर प्रस्तावित अर्बन प्लाजा, डिजिटल लाइब्रेरी, बुक कैफे, फूड कोर्ट, रूफटॉप टैरेस रेस्टोरेंट, बेसमेंट पार्किंग सहित बहुउद्देशीय भवन और अन्य सुविधाओं के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।

गंभीर रोगियों के इलाज के लिए मिले 19.12 लाख राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव के प्रयास से मिली सहायता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जौनपुर के नौ मरीजों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत हुई है। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चंद्र यादव के प्रयास से मरीजों को यह सहायता उपलब्ध कराई गई है। सहायता मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को महंगे इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से सुनील कुमार पाल निवासी सिद्दीकपुर को बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उपचार के लिए 2.50 लाख रुपये, डब्लू निवासी तारापुर को होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत हुई है। इसी तरह विनय कुमार सिंह निवासी ताहिरपुर को केजीएमयू लखनऊ के लिए 1.67 लाख 500 रुपये, दूधनाथ

निवासी सैदपुर गडउर को एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर के लिए 2.50 लाख रुपये, श्याम जी निवासी नदियापार को बीएचयू के कैंसर सेंटर के लिए 75 हजार रुपये तथा पप्पू निवासी मंडी नसीब खां और आशीष जायसवाल निवासी उर्दू बाजार को एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर में उपचार के लिए 2.50–2.50 लाख रुपये की सहायता मंजूर हुई है। इसके अलावा संगीता कुमारी निवासी पचोखर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में उपचार के लिए 1.20 लाख रुपये और आजाद निवासी तारापुर को बीएचयू के कैंसर सेंटर में उपचार के लिए 2.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इस प्रकार नौ लाभार्थियों के उपचार के लिए कुल 19 लाख 12 हजार 500 रुपये की सहायता स्वीकृत हुई है। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि गंभीर बीमारी से पीड़ित जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को उपचार के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मरीजों के परिजनों ने आर्थिक सहायता स्वीकृत कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव के प्रति आभार जताया। परिजनों ने कहा कि महंगे इलाज के बीच मिली इस सहायता से उन्हें बड़ी राहत मिली है और उपचार जारी रखने में मदद मिलेगी।

आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मागों को लेकर एडीएम को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर में शुक्रवार को 10 बजे निजी आईटीआई वेलफेयर एसोसिएशन ने सिद्धार्थ उपवन हाल में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जब तक उनकी लंबित मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे किसी भी प्रकार की जांच का बहिष्कार करेंगे। 11 बजे महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों ने एडीएम परमानंद झा को एक पत्र दिया महेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगों है कि 300 शिफ्टों को स्थायी मान्यता दी जाए। इसके अतिरिक्त, प्रवेश सीटें राज्य व्यावसायिक परीक्षण परिषद, लखनऊ द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से भरी जाएं और निर्धारित फीस सीधे संस्थान के बैंक खातों में भेजी जाए। अन्य

मांगों में प्राइवेट आईटीआई के मशीनरी और भवन में सुधार के लिए धनराशि का आवंटन, विद्युत कनेक्शन के मासिक बिलों की माफी और सोलर पैनल का कार्यान्वयन शामिल है। एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि निमी पोर्टल पर अनुदेशकों का अनुमोदन राजकीय आईटीआई के नोडल से हटाकर प्राइवेट आईटीआई के प्रबंधक से कराया जाए। एसोसिएशन ने प्राइवेट आईटीआई के अनुदेशकों और प्रशिक्षणार्थियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। साथ ही, प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित फीस को लागू करने की अपील की गई है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं, तो वे हड़ताल पर जाने पर विचार कर सकते हैं

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक सम्पन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर, जिलाधिकारीरू सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, श्रम एवं रोजगार, स्वास्थ्य, एमएसएमई, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, माध्यमिक शिक्षा, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, ऊर्जा, पर्यटन, कौशल विकास, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड पर जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षित स्तर से कम है अथवा जिन विभागों की रैंकिंग सी और डी श्रेणी में है, उनके अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों को व्यक्तिगत रुचि लेकर योजनाओं की प्रगति में सुधार लाने तथा प्रत्येक योजना की नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान पीएम–कुसुम योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए उप निदेशक कृषि को ई–रिक्शा के माध्यम से प्रचार कराने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने खराब ट्रांसफार्मरों की शिकायतों की जानकारी प्राप्त की तथा लंबित खराब ट्रांसफार्मरों को जल्द से जल्द ठीक कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की स्थिति की भी जानकारी ली। इस पर अवगत कराया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 20 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, कस्तूरबा गांधी विद्यालय सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीसी मनरेगा से पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रत्येक गांव में सूचना बोर्ड लगाए जाने की प्रगति की जानकारी ली तथा लंबित कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर अवगत कराने के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने स्नेक वेनम की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से डेंगू, मलेरिया सहित अन्य बीमारियों की जांच एवं उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीटी स्कैन, ऑक्सीजन प्लांट सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद में स्थापित सभी ऑक्सीजन प्लांटों को 10 से 15 दिन के भीतर क्रियाशील कराया जाए। फैमिली आईडी की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने डीपीआरओ, उपायुक्त उद्योग सहित संबंधित विभागों के सहयोग से अधिक से अधिक फैमिली आईडी जनरेट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उनके अधिकारियों को बैठक में बुलाकर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए जाएं। बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बारिश के बाद सभी विद्यालयों में आवश्यक पेंटिंग एवं रंगाई–पुताई का कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि समस्त विद्यालयों में सभी विद्यालयों की छतों की सफाई करवने हेतु निर्देशित किया जाए। पुराने एवं जर्जर विद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग से एस्टीमेट तैयार कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीएम पोषण योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मध्यान्ह भोजन के समय विद्यालयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता एवं अन्य व्यवस्थाओं की जांच की जाए। कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम विकास अधिकारी स्तर पर आवेदन लंबित हैं। जिसपर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि संबंधित ग्राम विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान विधवा पेंशन के आवेदनों के निस्तारण, आधार सीडिंग, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा पोषण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को शत–प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्रत्येक संकेतक की नियमित समीक्षा की जाए। जिन योजनाओं में प्रगति कम है, उनमें विशेष प्रयास कर अपेक्षित सुधार लाया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गंगाराम गौतम, पी.डी. के के पण्डये, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. अरुण यादव सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जौनपुर के केराकत में बिजली के झटके से 12 वर्षीय बालक किशन के दोनों पैर काटने के मामले में शुक्रवार को परिवार वालो ने प्रदर्शन करते हुए आर्थिक सहायता की मांग किया। परिवार ने इस हादसे के लिए बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और आर्थिक सहायता व कृषि भूमि आवंटन की मांग की है। जानकारी के अनुसार, 14 जुलाई को किशन बिजली के तार के संपर्क में आ गया था, जिससे उसे गंभीर झटका लगा। शुरुआती उपचार के बावजूद, उचित इलाज न मिलने के कारण उसके पैरों में गंभीर संक्रमण फैल गया। डॉक्टरों की सलाह पर उसके दोनों पैर काटने पड़े। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान, तत्कालीन उपजिलाधिकारी केराकत ने पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की तत्काल सहायता राशि देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, परिवार का आरोप है कि यह राशि उन्हें अब तक नहीं मिली है।पीड़ित परिवार ने बताया कि किशन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। परिवार ने उपचार में हुए खर्च, शारीरिक क्षति और आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बालक के पालन–पोषण के लिए कुछ कृषि भूमि आवंटित करने का भी अनुरोध किया है। परिवार ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है।

नगर पुलिस ने लूट एवं टप्पेबाजी गिरोह मे शामिल महिला समेत पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार

अयोध्या। कोतवाली नगर पुलिस ने लूट एवं टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए महिला समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से लूट के 2 लाख 5 हजार रुपये,तमंचा बरामद किया। बताया कि 20 अगस्त को मकबरा निवासी राम प्रसाद पाण्डेय ने थाना पर शिकायत दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति ने खुद को सूरज राय बताते हुए खुदाई में मिले चांदी के सिक्के, सोने की माला के दाने और अन्य जेवरात बताकर उन्हें बेचने का झांसा दिया।आरोपी ने पांच से छह लाख रुपये की जरूरत बताई और बाद में दो लाख रुपये लेकर आने के लिए कहा।शिकायत के अनुसार, जब पीड़ित दो लाख रुपये लेकर रायबरेली रोड पहुंचा तो वहां चार लोग मिले।शिकायतकर्ता ने बताया कि इसी दौरान असलहे के बल पर उससे दो लाख रुपये छीनकर आरोपी फरार हो गए। इस मौके पर एसपी सिटी श्री त्रिपाठी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम, स्वाट टीम और सर्विलांस टीम को घटना की खुलाशे के लिए लगाया गया।पुलिस ने शुक्रवार सुबह करीब 4:14 बजे रायबरेली रोड स्थित उसरू नहर के पास एमबी पब्लिक स्कूल के सामने से पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया।बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सूरज राय निवासी बहराइच, मोहन राय निवासी इटावा, राजू राय निवासी उन्नाव, करन राय निवासी इटावा तथा पिंकी देवी निवासी उन्नाव के रूप में हुई है।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गये आरोपियों के विरुद्ध अयोध्या के अलावा अलीगढ़ में भी मुकदमे दर्ज हैं।सूरज राय के विरुद्ध हरदोई और लखनऊ में भी पूर्व में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मनोज शर्मा के अलावा कोतवाली नगर में तैनात निरीक्षक प्रदीप यादव,उप निरीक्षक अमरेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम उप निरीक्षक शुभम सिंह,अखिलेश तिवारी,आदर्श विक्रम सिंह, संदीप कुमार,शैलेश कुमार, महिला उप निरीक्षक किरण पाल सहित अन्य पुलिस कर्मियों की सहनीय भूमिका रही।

मंडलायुक्त राजेश कुमार ने अटल आवासीय विद्यालय का किया औचक निरीक्षण

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। मंडलायुक्त अयोध्या राजेश कुमार ने अटल आवासीय विद्यालय,अयोध्या का औचक निरीक्षण कर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही शैक्षणिक, आवासीय एवं अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता परखी। उन्होंने विद्यालय की कक्षाओं,मेस, छात्रावास एवं परिसर का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मंडलायुक्त ने विद्यार्थियों को पढ़ाया सामाजिक विषय निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त राजेश कुमार ने कक्षा–10 के विद्यार्थियों को सामाजिक विषय का अध्यापन भी कराया।उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी पढ़ाई, विद्यालय की व्यवस्थाओं, भोजन एवं छात्रावास से संबंधित अनुभवों की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक संवाद करते हुए अपनी जिज्ञासाएं एवं अनुभव मंडलायुक्त के साथ साझा किए।मंडलायुक्त ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन,अनुशासन एवं समय के सदुपयोग के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और निरंतर सीखने की प्रवृत्ति ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य निर्धारित कर पूरे मनोयोग से अध्ययन करने का संदेश दिया।इस अवसर पर वर्ष 2026 में कक्षा–10 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष चार मेधावी विद्यार्थियों को मंडलायुक्त द्वारा पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए अन्य विद्यार्थियों को भी उनसे प्रेरणा लेने के लिए कहा।मंडलायुक्त ने विद्यार्थियों को पठन–पाठन सामग्री भी वितरित की तथा निरंतर मेहनत, अनुशासन एवं लगन के साथ अध्ययन करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मंडलायुक्त ने छात्र–छात्राओं के साथ भोजन कर उसकी गुणवत्ता को भी परखा। उन्होंने मेस में साफ–सफाई, पेयजल तथा खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को निर्धारित मेनू चार्ट के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। भोजन की गुणवत्ता के साथ–साथ मेस एवं छात्रावास परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।इस मौके पर निरीक्षण के दौरान उपश्रमायुक्त अमित मिश्रा,उप जिलाधिकारी रुदौली विनोद कुमार गुप्ता तथा श्रम प्रवर्तन अधिकारी गौरव गुप्ता एवं सत्येंद्र प्रताप विद्यालय के प्राचार्य पी.के. नारायणन, प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार,शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

'जनसुनवाई में जिलाधिकारी ने सुनी 94 शिकायतें'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा ने आमजन की समस्याओं को सुना। शुक्रवार को जन सुनवाई में कुल 94 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके त्वरित निस्तारण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक शिकायत का

निस्तारण समयबद्व और गुणवत्तापूर्ण पूर्ण हो। जनसुनवाई में प्राप्त कुछ शिकायतों का जिलाधिकारी ने मौके पर ही समाधान किया। जनसुनवाई मे अतिरिक्त मजिस्ट्रेट मयंक कुंडू व अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुनिया का सबसे सस्ता होगा 50वां अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला

भदोही, (संवाददाता)। आगामी 4 से 7 अक्तूबर तक भदोही में लगने वाला 50वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला दुनिया का सबसे सस्ता कालीन मेला होगा। आयोजन समिति कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने दावा किया है कि भदोही एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाला यह गोल्डन जुबली मेला ऐतिहासिक आयोजन साबित होगा। इसके लिए स्टॉलों की बुकिंग बृहस्पतिवार से शुरू हो जाएगी। मेले में छोटे व मझोले निर्यातक भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए स्टॉल की दरें इस साल काफी कम रखी गई हैं। सीईपीसी इसे सर्वाधिक भागीदारी वाला कालीन मेला बनाने के प्रयास में जुटा है। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) इस बार के कालीन मेले को बेहतर बनाने के प्रयास में जुटी है। छोटे और मझोले कालीन उत्पादक और निर्यातक भी इसमें भाग ले सकें, इसके लिए श्रेणी बनाकर स्टॉल की कीमतें भी काफी कम की गई हैं। स्टॉलों की बुकिंग 20 अगस्त को सुबह 11.30 बजे शुरू होंगी। लोगों को शिकायत न हो, इसके लिए पहले आओ–पहले पाओ को आधार बनाया गया है। इसकी जानकारी लोगों को तीन दिन पहले ही दे दी गई है, ताकि लोग पहले से बुकिंग के लिए तैयार रहें। सीईपीसी ने भदोही एक्सपो मार्ट में भूतल हाल, भूतल शॉप, प्रथम तल शॉप, ऊपरी हाल और द्वितीय तल शॉप कुल पांच श्रेणियों में स्टालों को बांटा है। सबसे महंगा 6 हजार प्रति वर्ग मीटर का भूतल शॉप है। भूतल हाल पर स्टाल के लिए प्रति वर्ग मीटर साढ़े पांच हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

सरयू खतरे के निशान से 37 सेमी ऊपर, लहरें मकानों से टकराईं, गांवों में दहशत

गोरखपुर, (संवाददाता)। खतरे के निशान से 37 सेंटीमीटर ऊपर बह रही सरयू नदी ने तटवर्ती गांवों में तबाही मचानी शुरू कर दी है। कुदरहा, दुबौलिया और विक्रमजोत ब्लॉक के कई गांवों में नदी का पानी घरों से टकराकर हिलोरे मार रहा है। कई स्थानों पर कटान तेज होने से तटबंधों पर भी दबाव बढ़ गया है। नदी के हिलोरों के घरों से टकराने से ग्रामीणों में दहशत है। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ शरणालयों की व्यवस्था दुरुस्त कराई है। बुधवार को सुबह 10 बजे सरयू का जलस्तर स्थिर रहा लेकिन शाम पांच बजे अयोध्या पुल पर जलस्तर 93.10 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का निशान 92.73 मीटर है। नदी की धारा तेज होने के कारण तटवर्ती इलाकों में खतरा बरकरार है। दुबौलिया क्षेत्र के सुविका बाबू और आंशिक टेढ़वा गांव में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। चारपाई, चारा मशीन समेत गृहस्थी का सामान पानी में डूब गया है। ग्रामीण खाद्य सामग्री को कच्चे–पक्के मकानों के बड़ेर और छज्जों पर सुरक्षित रखने को मजबूर हैं। घरों में पानी भरने ेसे खाना पकाने में भी परेशानी हो रही है। आवागमन के लिए इन गांवों में पांच मोटरबोट लगाई गई हैं। स्कूली बच्चे भी मोटरबोट से विद्यालय जाने को मजबूर हैं। पानी भरने से कुछ छप्पर के घर गिरने लगे हैं। सरयू की दो धाराओं के बीच बसे देवारागंगबरार, कुर्मियाना, सतहा, दस नंबर पुरवा, भुवरिया, विशुनदासपुर की अनुसूचित बस्ती, श्रीराम पुरवा, बरदियालोहार और पूरे मोतीराम की ओर भी पानी फैल रहा है। माझा क्षेत्र की फसलें जलमग्न हो गई हैं। कटरिया–चांदपुर तटबंध पर खजांचीपुर से खलवा गांव तक करीब दो किलोमीटर क्षेत्र में नदी का दबाव बढ़ गया है। उमरिया रिंगबांध भी खतरे में है। नदी कटान करते हुए बांध के करीब पहुंच गई है। कटान स्थल पर लगातार पांचवें दिन मरम्मत कार्य जारी रहा। ग्रामीणों का कहना है कि रिंगबांध क्षतिग्रस्त हुआ तो उमरिया, किशुनपुर, कनघुसरा, नाउपुरवा और कोईरीपुरवा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच सकता है। विक्रमजोत–धुसवां तटबंध पर नदी का दबाव रू विक्रमजोत। सरयू नदी का दबाव विक्रमजोत–धुसवां तटबंध पर भी बढ़ गया है। दुधौरा पूरेराम गांव के पास नदी तटबंध से सटकर बह रही है। आसपास कटान भी हो रही है। ग्रामीणों ने तटबंध पर दो किलोमीटर के दायरे में स्थापित दो बाढ़ चौकियों पर कर्मचारियों की नियमित मौजूदगी नहीं होने का आरोप लगाया है।

संगठन में ही पत्रकारों की ताकत,सुविधाओं के लिए एकजुट होकर उठाएं आवाज – दिलशाद खान

अयोध्या।पत्रकार चौराहे पर पत्रकारों की बैठक आयोजित हुई।बैठक में उत्तराखंड से पहुंचे ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद खान का प्रदेश अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया।राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद खान ने कहा कि संगठन में ही ताकत है। यदि पत्रकार संगठित रहेंगे तो अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज उठा सकेंगे।उन्होंने पत्रकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाते हुए कैशलेस इलाज की सुविधा दिए जाने पर भी जोर दिया।इस दौरान दिलशाद खान ने सुबोध श्रीवास्तव को संगठन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा। संगठन के विस्तार के लिए रूपेश श्रीवास्तव को अयोध्या का जिलाध्यक्ष तथा आकाश सोनी को जोनल कोऑर्डिनेटर , राजेंद्र दुबे राजू प्रदेश संगठन मंत्री,समीर शाही जिला प्रभारी, सचिन सरीन जिला उपाध्यक्ष, राकेश सिंह महानगर अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव अज्जू संरक्षक, बृजेश तिवारी जिला सचिव प्रशांत शुक्ला मंडल अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही अन्य पत्रकारों को विभिन्न पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव ने कहा कि जल्द ही संगठन का प्रदेश एवं जिला स्तर पर विस्तार किया जाएगा।उन्होंने पत्रकारों से संगठन को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया।बैठक में अश्वनी सोनकर, वैभव श्रीवास्तव,नरेंद्र मिश्रा,राजेश श्रीवास्तव,तुफैल अहमद, महेंद्र उपाध्याय,सीएम श्रीवास्तव, भानु प्रताप सिंह बमबम यादव, करण प्रजापति, गुलजार खान, आशु श्रीवास्तव, शिवदयाल वर्मा, ज्ञानेंद्र मिश्रा के अलावा दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे।

एचआरपी की लिस्ट में सबसे ऊपर कम वजन वाली महिलाएं

भदोही, (संवाददाता)। बदलती जीवनशैली, तनाव, खानपान और देर से शादी के कारण जिले में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी (एचआरपी) के मामले तेजी से बढ़े हैं। यहां हर 15 में से पांच महिलाएं हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में हैं। पहले यह आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन जैसे–जैसे समय बदल रहा है, इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिन प्रसूता महिलाओं की वजन 35 किलोग्राम से कम है, वह एचआरपी की श्रेणी में निश्चित तौर पर होंगी। इसका मुख्य कारण पौष्टिक भोजन न करना है। जिले में हर महीने औसतन 700 से 800 की ओपीडी होती हैं। आम तौर पर देखा जाता है कि गर्भधारण के बाद महिलाएं आराम करने लगती है। इसका परिणाम आगे चलकर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो हर महीने औसतन 700 से 800 प्रसव होते हैं। इसमें निजी व सरकारी अस्पतालों को मिलाकर औसतन 70 फीसदी सीजर मामले होते हैं। यदि प्रसूता चाहे तो कुछ हद तक इसे रोका जा सकता है। इसका ग्राफ 50 फीसदी से नीचे आ सकता है। जिला अस्पताल के स्त्री रोग एवं प्रसूता विशेषज्ञ डॉ. मुकेश प्रजापति ने बताया कि नियमित जांच, संतुलित आहार और व्यायाम से एचआरपी के जोखिम कम किए जा सकते हैं। समय पर अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर, मधुमेह की जांच होनी चाहिए। ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला अस्पताल तक यह व्यवस्था है। आशा कार्यकर्ता नियमित रूप से गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग करती हैं। मातृत्व वंदन योजना के तहत निशुल्क अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है।

राप्ती में नहाने गया 10वीं का छात्र प्रिंस डूबा, हत्या की आशंका

गोरखपुर, (संवाददाता)। राप्ती नदी में नहाने गए 10वीं के छात्र प्रिंस कुमार (16) के लापता होने के बाद बुधवार को पथरा में जमकर हंगामा हुआ। छात्र के परिजन ने उसके साथ गए दो दोस्तों पर हत्या कर शव नदी में गायब करने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने दोपहर तीन बजे मुख्य सड़क जाम कर दिया। एसडीएम सदर, सीओ कैंट समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों के समझाने के बाद रात नौ बजे जाम समाप्त हुआ। रामगढ़ताल क्षेत्र के सेमरा देवी प्रसाद छोटका पथरा निवासी सत्यपाल निषाद का बेटा प्रिंस एमजी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ता था। मंगलवार दोपहर स्कूल से लौटने के बाद राजघाट क्षेत्र के चकरा दोयम निवासी दो साथी करीब साढ़े तीन बजे स्कूटी से उसके घर पहुंचे। दोनों प्रिंस को अपने साथ राप्ती नदी की ओर ले गए। दोस्तों के मुताबिक, नदी में नहाते समय प्रिंस गहरे पानी में डूब गया। इसके बाद दोनों उसके कपड़े और मोबाइल लेकर घर पहुंचे और परिजन को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से नदी में तलाश शुरू की लेकिन बुधवार रात तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। नदी किनारे उसकी चप्पल और अमरूतानी में कपड़े व मोबाइल बरामद हुए। परिजन का कहना है कि प्रिंस और दोनों दोस्तों के बीच करीब तीन महीने पहले विवाद हुआ था। तीन दिन पहले और घटना वाले दिन भी विवाद की बात सामने आई। इसी आधार पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बुधवार दोपहर तीन बजे से परिजन ने पथरा के पास सड़क जाम कर दी। एसडीएम सदर, सीओ कैंट समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।

सरयू के बढ़ते जलस्तर के बीच अयोध्या में बाढ़ नियंत्रण में, योगी सरकार की तैयारी आई काम

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सरयू (घाघरा) नदी के जलस्तर में वृद्धि के बावजूद योगी आदित्यनाथ सरकार की पूर्व तैयारी और सतर्क प्रशासन के कारण जिले में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण बना हुआ है।जनपद में घाघरा नदी पर दो प्रमुख तटबंध सुरक्षित हैं।रौनाही तटबंध दायें तट पर 14.550 किलोमीटर लंबा है तथा अयोध्या–बिल्वहरिघाट तटबंध 13.140 किलोमीटर का है।इसके अतिरिक्त तमसा नदी (मडहा) पर गोसाईगंज शहर की सुरक्षा के लिए 5.340 किलोमीटर लंबा तटबंध भी सुरक्षित है। योगी सरकार के नेतृत्व में इन तटबंधों की नियमित मरम्मत और मजबूती के कारण बाढ़ का पानी नियंत्रित रहा और बड़े पैमाने पर नुकसान से बचा जा सका। वर्तमान में जनपद के कुल 11 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें तहसील सदर के चार ग्राम मांझा मूडाडीहा अयोध्या, मांझा मड़ना, मांझा रामपुरपुवारी और मांझा काजीपुर, तहसील सोहावल का एक ग्राम मांझा कलाय तथा तहसील रुदौली के छह ग्राम मुजेहना मजरे सरायनासिर, पूरे महंगू मजरे पसौवा, पूरे महंगू मजरे सण्डरी, अब्बूपुर मजरे बरई, कैथी मांझा मजरे कैथी और सुलेमपुर मजरे उधरीरा शामिल हैं। शहरी क्षेत्र में जलभराव की कोई स्थिति नहीं है तथा कृषि क्षति की कोई सूचना भी नहीं मिली है।बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने अब तक कुल 2370 बाढ़ राहत किट वितरित किए हैं। इनमें तहसील सदर में 1500, रूदौली में 645 और सोहावल में 225 किट शामिल हैं। साथ ही 1450 लंच पैकेट तथा प्रभावित पशुओं के चारे के लिए 350 कुंतल भूसा भी वितरित किया गया है। योगी सरकार की आपदा प्रबंधन नीति के तहत राहत सामग्री का वितरण पारदर्शी और त्वरित तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है।जिले में कुल 14 बाढ़ शरणालय चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें आवश्यकतानुसार क्रियाशील किया जाता है। वर्तमान में सोहावल तहसील स्थित सहारा बाग में बाढ़ शरणालयध्शेल्टरहोम क्रियाशील है, जहां 100 बाढ़ प्रभावित व्यक्ति रह रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में तहसील सदर में 6, रूदौली में 3 तथा सोहावल में 1 कुल 10 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। इन चौकियों पर राजस्व, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। आवागमन के लिए 18 नावें भी संचालित की जा रही हैं।स्वास्थ्य विभाग द्वारा बचाव और राहत हेतु 37 टीमें गठित की गई हैं, जिन्होंने भ्रमणशील रहकर अब तक 1224 ओआरएस पैकेट और 2912 क्लोरीन की टैबलेट का वितरण किया है। पशु चिकित्सा विभाग की 21 टीमें प्रभावित ग्रामों में पशु टीकाकरण, शिविर लगाकर उपचार और जांच का कार्य कर रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक विवरण के अनुसार नदी का खतरे का जलस्तर 92.730 मीटर है, जबकि 20 अगस्त को रात्रि 8 बजे जलस्तर 93.040 मीटर दर्ज किया गया। वर्ष 2026 में अधिकतम जलस्तर 93.100 मीटर तक पहुंच गया था, जो खतरे के निशान से मात्र 0.370 मीटर ऊपर था। वर्तमान में यह स्तर खतरे के निशान से 0.310 मीटर ऊपर स्थिर है। वर्ष 2009 में दर्ज अधिकतम जलस्तर 94.010 मीटर की तुलना में स्थिति काफी नियंत्रित है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने सभी संबंधित विभागों को बाढ़ राहत कार्यों के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। तहसील सदर, सोहावल और रूदौली के उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार लगातार निगरानी कर रहे हैं तथा खाद्यान्न व भूसे का वितरण आवश्यकतानुसार कराया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को सुचारु बनाने के लिए समयबद्ध निर्देश दिए हैं। तटबंधों की सुरक्षा, राहत सामग्री का पर्याप्त भंडारण, स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा टीमें तथा निरंतर निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक सतर्कता का परिणाम हैं।जनपद प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने का कार्य निर्बाध रूप से जारी है।

अर्थव्यवस्था में अहम योगदान के बाद भी स्वर्णकार समाज उपेक्षित – राकेश

वाराणसी, (संवाददाता)। स्वर्णकार समाज के लोगों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सोनार नरहरी सेना के लोगों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो संगठन के लोग प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। स्वर्णकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश वर्मा ने कहा कि स्वर्णकार समाज देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बावजूद समाज आज उपेक्षा का शिकार है। जिलाध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि लंबे समय से समाज की समस्याओं और मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, लेकिन अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। मांगों में स्वर्णकला बोर्ड का गठन, साहूकार लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस में प्राथमिकता, मुद्रा योजना के तहत गोल्ड लोन और स्वर्णकार समाज की सुरक्षा आदि मांगें शामिल रहीं। चेताया कि यदि 15 दिन के अंदर मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए।

रामगढ़ताल में चलेगी 50 सीटर एसी फेरी, जलमार्ग से जुड़ेंगे चिड़ियाघर, कन्वेंशन सेंटर और नया सवेरा

गोरखपुर, (संवाददाता)। रामगढ़ताल की सैर अब और खास होने जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ताल पर 50 यात्रियों की क्षमता वाली वातानुकूलित फेरी सेवा शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए ई–निविदा जारी कर दी गई है। करीब 2.59 करोड़ रुपये की परियोजना से दो फ्लोटिंग जेट्टी बनाई जाएंगी जो ताल के प्रमुख पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ेंगी। प्रस्तावित फेरी सेवा आरकेबीके जंक्शन, गोरखपुर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर एवं एलीट क्लब, नया सवेरा, प्रस्तावित बैंबू रेस्टोरेंट, चिड़ियाघर और सहारा एस्टेट के पास बनने वाली नई जेट्टी को जोड़ेगी। इससे लोग सड़क के बजाय ताल के रास्ते इन स्थानों तक पहुंच सकेंगे। करीब 1800 एकड़ में फैले रामगढ़ताल के पर्यटन को इससे नया आयाम मिलने की उम्मीद है। फेरी में यात्रियों की सुरक्षा, नेविगेशन और सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम होंगे। ताल में दो फ्लोटिंग जेट्टी बनाई जाएंगी। प्रत्येक जेट्टी पर टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय और शौचालय की सुविधा होगी। फेरी और जेट्टी का डिजाइन व निर्माण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के दिशा–निर्देशों और पोत सुरक्षा मानकों के अनुसार होगा। ई–निविदा के जरिये चयनित एजेंसी फेरी और जेट्टी का निर्माण, संचालन और रखरखाव 10 साल तक करेगी। अवधि को पांच साल तक बढ़ाया जा सकेगा। एजेंसी को टिकटिंग, फेरी पर खान–पान और विज्ञापन का अधिकार मिलेगा। टिकट की दर जीडीए तय करेगा। लाइसेंस अवधि पूरी होने पर सभी संसाधनों का स्वामित्व जीडीए के पास लौट आएगा। एजेंसी का चयन खुली और प्रतिस्पर्धी ई–निविदा के जरिए लीस्ट कॉस्ट सिलेक्शन प्रक्रिया से होगा। एजेंसी की नियुक्ति के 180 दिनों के भीतर फेरी और दोनों जेट्टी को तैयार कर सेवा शुरू करनी होगी। परियोजना की अनुमानित विकास लागत 2.59 करोड़ रुपये है, जिसे निर्माण अवधि में जीडीए चयनित एजेंसी को उपलब्ध कराएगा। जीडीए अधिकारियों के अनुसार, फेरी सेवा शुरू होने से रामगढ़ताल के आसपास के पर्यटन स्थलों को एक–दूसरे से जोड़ने के साथ लोगों को घूमने का नया विकल्प मिलेगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।